हडको
hudco
A NAVRATNA CPSE

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम

विकासशील भारत के लिए संपत्ति का निर्माण

निवेशकों की प्रस्तुति और प्रदर्शन के मुख्य अंश
तिमाही 2 और छमाही 1 वित्त वर्ष 25

सामग्री की तालिका

01
हडको, एक अद्वितीय संस्था

02
प्रचालन प्रदर्शन

03
वित्तीय प्रदर्शन

- बोरोइंग प्रोफ़ाइल
- परिसंपत्ति की गुणवत्ता
- प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

04
सेक्टर आउटलुक और अवसर

हडको - एक अद्‌वितीय संस्था

- तकनीकी-वित्तीय संस्थान के रूप में 5 दशक से अधिक का अनुभव।
- वित्तपोषण, परामर्श और क्षमता निर्माण आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संपूर्ण परिदृश्य को समर्थन।
- राज्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंधों के साथ बहुक्षेत्रीय फोकस।
- भारत सरकार के प्रयासों को पूरा करने में रणनीतिक साझेदार - सभी के लिए आवास, स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, आदि।
- भारत सरकार के 75% स्वामित्व वाली सूचीबद्‌ध कंपनी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत एक नवरत्न सीपीएसई।
- "सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता" के आदर्श वाक्य के साथ लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी

यात्रा

1970-1980
- 1970: कंपनी अधिनियम के तहत निगमन
- इक्विटी: ₹2 करोड़
- ग्रामीण आवास का वित्तपोषण
- डिजाइन एवं विकास गतिविधियाँ

1980-1990
- 1985: एचएसएमआई
- 1989: एक्सक्लूसिव अर्बन इन्फ्रा विंडो

1990-2000
- 1998: 2एमएचपी में महत्वपूर्ण भूमिका
- 1999-2000: शीर्ष 10 सार्वजनिक उपक्रमों को प्रधानमंत्री का पुरस्कार
- 1996: सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई)

2000-2010
- 2000: हडको निवास
- 2001: अधिकृत पूंजी बढ़ाकर ₹2500 करोड़ कर दी गई 2002: अनुसूची-ए
- 2004: मिनीरत्न-I

2010-2020
- 2011-2016-कर मुक्त बांड का सार्वजनिक निर्गम
- 2015-16 क्रेडिट रेटिंग को "AAA" में अपग्रेड किया गया
- 2017: 10.19% की सार्वजनिक सूची
- लगातार 'उत्कृष्ट' MoU रेटिंग प्राप्त की

2020- अब तक
- 2023-24: सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% की गई।
- 2023-24 - ₹830.79 करोड़ का सर्वकालिक उच्चतम लाभांश

2024-25:
- **नवरत्न का दर्जा प्राप्त**
- **एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत**

नवरत्न दर्जा: अप्रैल, 2024 में प्रदान किया गया
- **भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए दूसरी सर्वोच्च मान्यता**

2 एमएचपी – 2 मिलियन आवास कार्यक्रम
एचएसएमआई - मानव बसाहट प्रबंधन संस्थान

पिछले एक वर्ष के दौरान प्रमुख पहल

	समस्याएँ	कार्रवाई की
1	नवरत्न स्थिति	हडको को विशिष्ट सीपीएसई में स्थान मिला, ब्रांड छवि में सुधार हुआ, प्रचालन और वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि हुई।
2	एनबीएफसी-आईएफसी पंजीकरण	• देश की अग्रणी सरकारी एनबीएफसी में प्रमुख स्थान • दीर्घकालिक अवसंरचना ऋण अवसर, जिसमें डीईए की सामंजस्यपूर्ण सूची के अंतर्गत आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं सहित, अवसंरचना परियोजनाओं की विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
3	पिछले आधे दशक से बीएस का आकार स्थिर	सितंबर 2023 में ₹81,594 करोड़ से सितंबर 2024 में ऋण पुस्तिका बढ़कर ₹ 1,11,068 करोड़ हो गई, 36% की वृद्धि
4	समझौता ज्ञापन	• हडको के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना: बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों में उभरती जरूरतों और अवसरों को पूरा करना। • व्यापक वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रचालन पहुंच को बढ़ाना।
5	निधियों की लागत कम करना	• जेपीवाई ईसीबी ऋण और एफसीएनआर(बी) ऋण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति स्थापित करना। • वृद्धिशील लागत वित्त वर्ष 2023 में 7.46% से घटकर वित्त वर्ष 2024 के दौरान 7.10% हो गई और H1FY24 के दौरान 7.28% से घटकर H1FY25 के दौरान 6.99% हो गई।
6	पुरानी नीतियों का अद्यतनीकरण	ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के अनुरूप नवीन ऋण उत्पादों की शुरूआत तथा टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) में कमी
7	मानव संसाधन मुद्दे	पेशेवरों की भर्ती, सभी स्तरों पर पदोन्नति, परिचालन दक्षता के लिए विभागों का पुनर्गठन
8	स्ट्रेस्ड असेट का समाधान	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीए मामलों से लगभग ₹ 456 करोड़ और वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में ₹ 255 करोड़ वसूले गए।

प्रमुख ताकतें

अखिल भारतीय उपस्थिति, राज्यों के साथ मजबूत संबंध

भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ - सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन आदि में की रोल।

मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता - सबसे कम एनपीए

मजबूत वित्तीय अनुपात - सुसंगत लाभप्रदता

उच्चतम क्रेडिट रेटिंग:
घरेलू-एएए
अंतर्राष्ट्रीय-संप्रभु

प्रशिक्षण और परामर्श सेवाओं सहित मूल्य वर्धित सेवाएं

'नवरत्न' कंपनी
और
आवास एवं अवसंरचना क्षेत्र में रणनीतिक खिलाड़ी

विकसित भारत के लिए सतत परिसंपत्ति निर्माण हेतु 360° भागीदारी

hudco
A NAVRATNA CPSE

वित्तपोषण

- किफायती आवास
- समकक्ष अनुदान - पीएमएवाई
- आधारभूत संरचना :
  - सामाजिक इन्फ्रा - अस्पताल, सरकारी भवन, जल आपूर्ति;
  - वाणिज्यिक अवसंरचना - सड़कें, राजमार्ग, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बंदरगाह, ऊर्जा
- भूमि अधिग्रहण

भारत सरकार की योजनाएं

- पीएमएवाई- शहरी और ग्रामीण
- स्मार्ट सिटी
- अमृत
- स्वच्छ भारत मिशन
- जल जीवन मिशन

प्रधान मंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana

SMART CITIES MISSION

अमृत Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

Har Ghar Jal Jal Jeevan Mission

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

BHARATMALA ROAD TO PROSPERITY

कंसल्टेंसी

- वास्तु
- शहरी & स्थानीय योजना
- मूल्यांकन & निगरानी
- संपत्ति मुद्रीकरण
- पर्यावरण अध्ययन

क्षमता निर्माण

- पेशेवरों का प्रशिक्षण / इन हाऊस कर्मचारी
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- शहरी क्षेत्र में समर्थन अनुसंधान.

उधार लेने वाले भागीदार: केंद्र/राज्य सरकारें, राज्य की सार्वजनिक एजेंसियां, यूएलबी और विशिष्ट संस्थाएं

अखिल भारतीय उपस्थिति

(सक्रिय करना - व्यवसाय विविधीकरण, बढ़ी हुई ब्रांड पहचान, सरकारी पहलों का बेहतर लाभ उठाना और क्षेत्रीय गतिशीलता को अपनाना)

- **पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में।**
- **पूरे भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 विकास कार्यालय।**
- **हडको की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शाखा - मानव बस्ती प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई), नई दिल्ली**
- **कर्मचारी संख्या (सितंबर, 2024 तक)- 587**
  - विविध पृष्ठभूमि के अधिकारी – 504 [तकनीकी, वित्त, कानूनी, मानव संसाधन, सामाजिक विज्ञान और आईटी]
  - महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना - 31% (184) महिला कर्मचारी

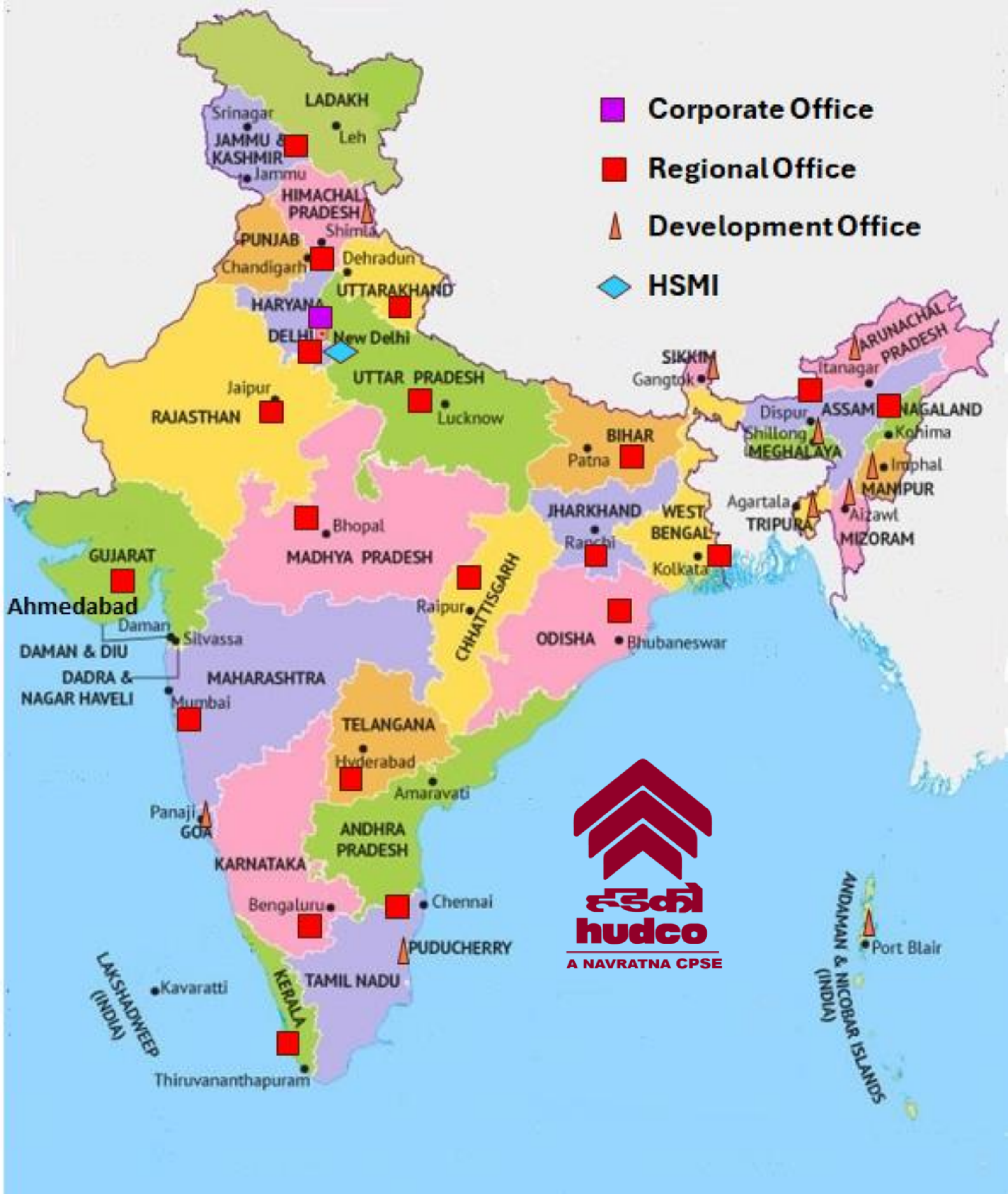

उच्चतम क्रेडिट रेटिंग

दीर्घावधि के लिए AAA रेटिंग ऋण

देखभाल	आईआरआरपीएल	आई.सी.आर.ए.

बीबीबी+	बीबीबी-	बी ए ए3
जेसीआरए *	फिच रेटिंग	मूडीज

* पारंपरिक रेटिंग से दो पायदान ऊपर

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संप्रभु रेटिंग के बराबर

तिमाही2 वित्त वर्ष 25 के अनुसार शेयरधारकों की संभावना

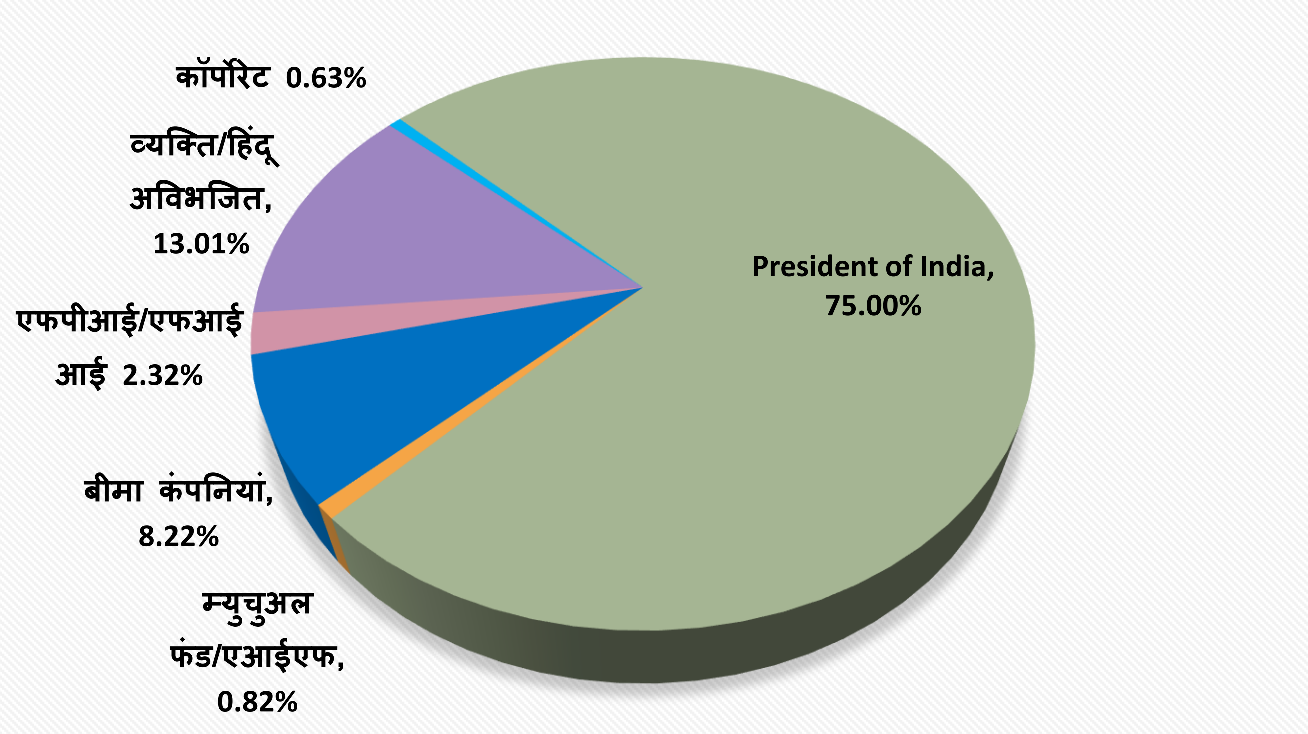

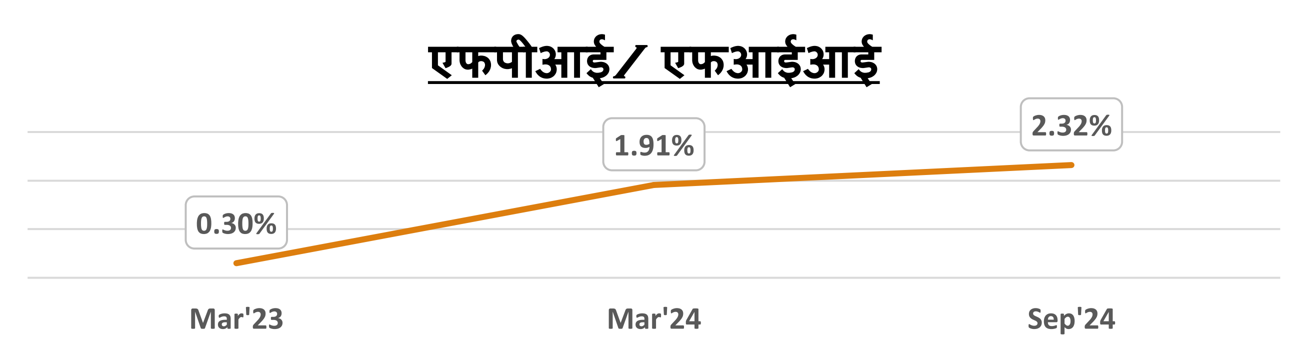

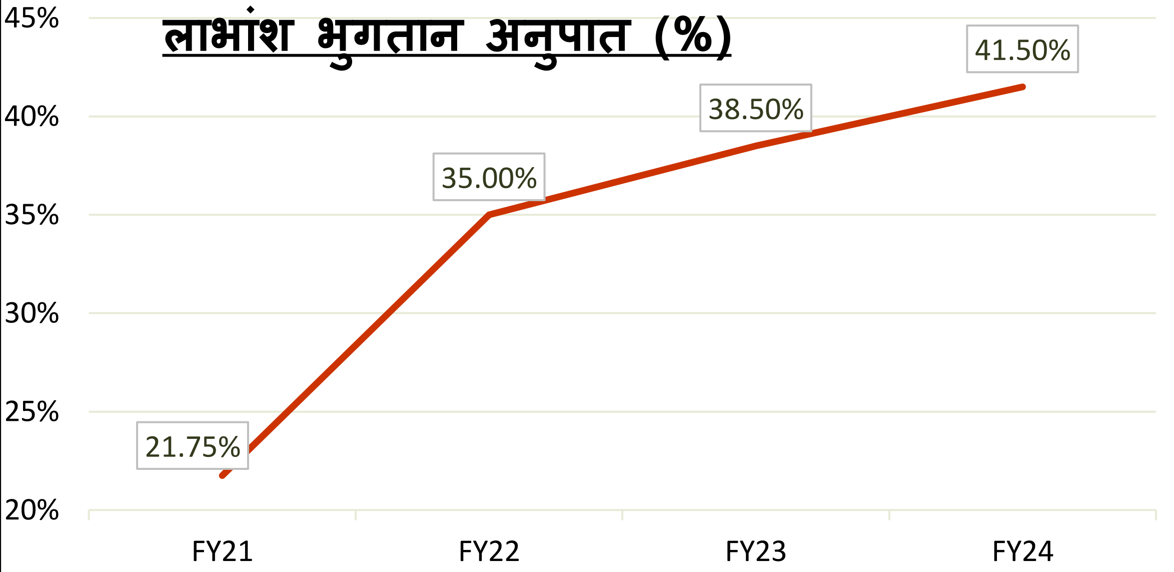

हडको में हितधारकों का विश्वास

बाजार पूंजीकरण

(₹ करोड़)

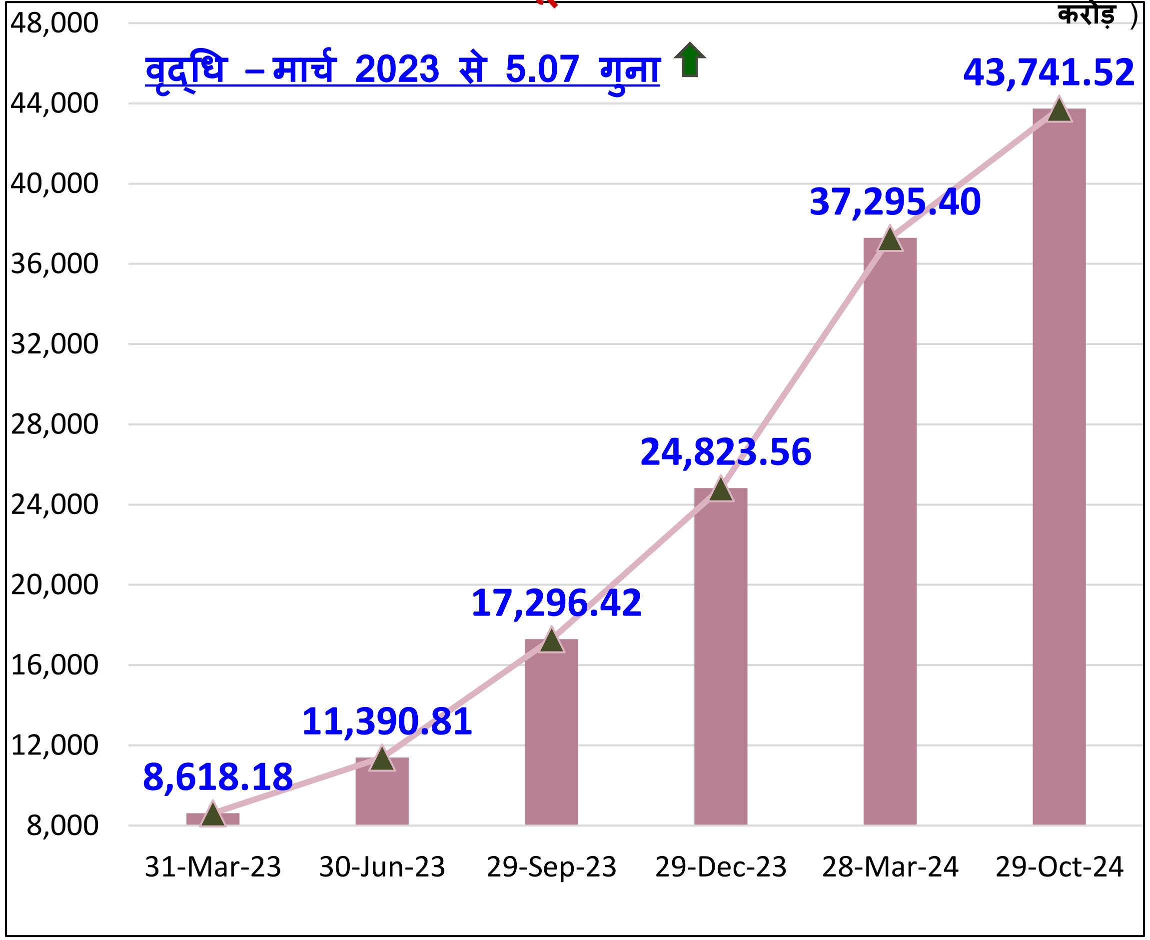

मार्केट कैप के हिसाब से शीर्ष 200 कंपनियों में शामिल (मार्च, 2024 तक)

प्रति शेयर आय – ₹ 12.46 (वार्षिक)

प्रति शेयर बुक वैल्यू – ₹ 85.54

प्रचालन प्रदर्शन

- मुख्य अंश
- श्रेणीवार स्वीकृतियां
- श्रेणीवार संवितरण
- ऋण पोर्टफोलियो

प्रमुख ऑपरेशनल विशेषताएं

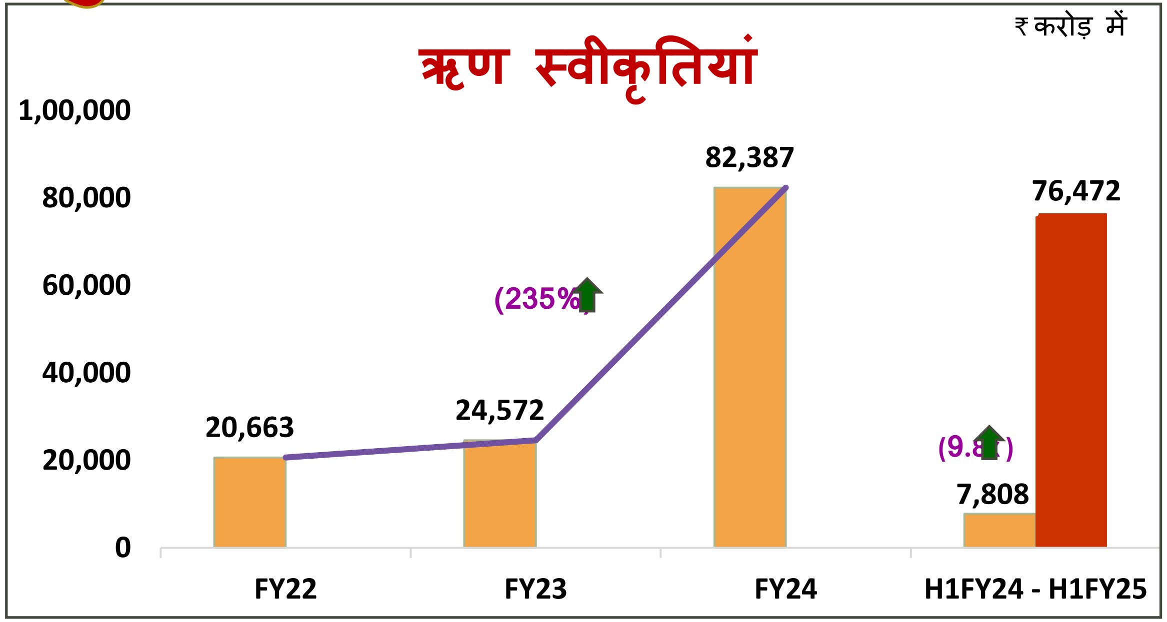

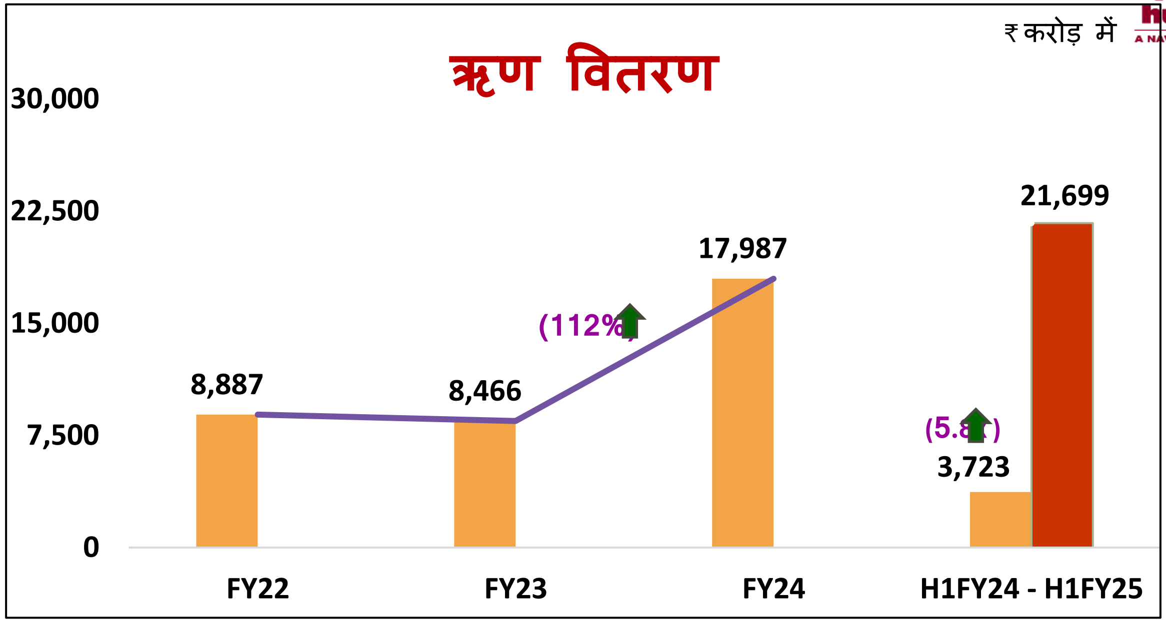

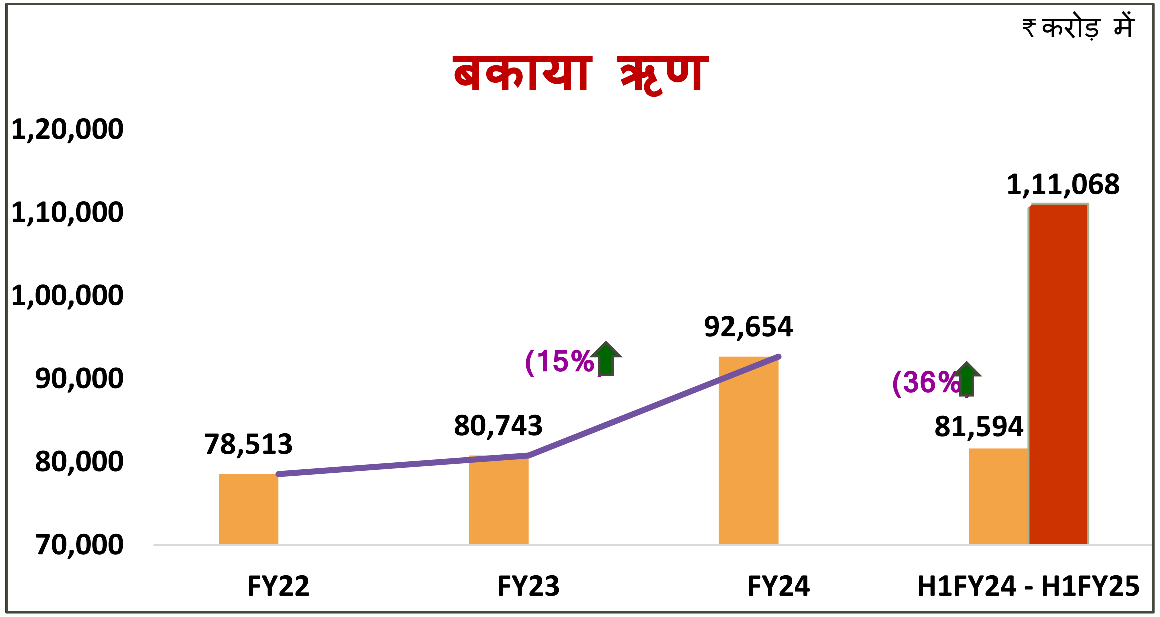

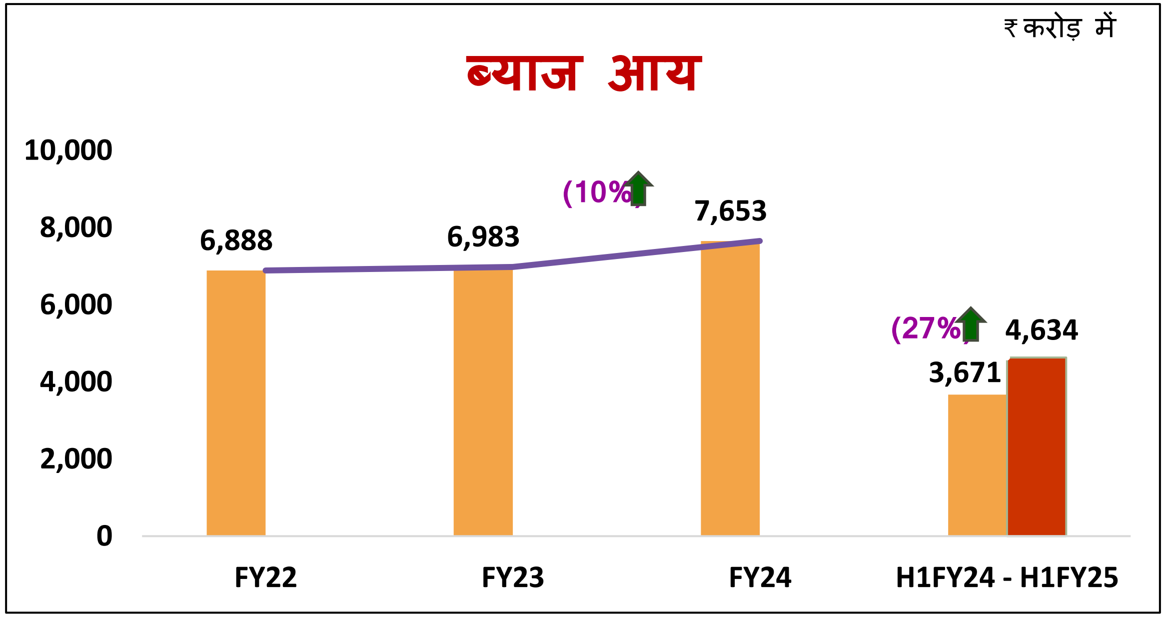

ऋण पोर्टफोलियो

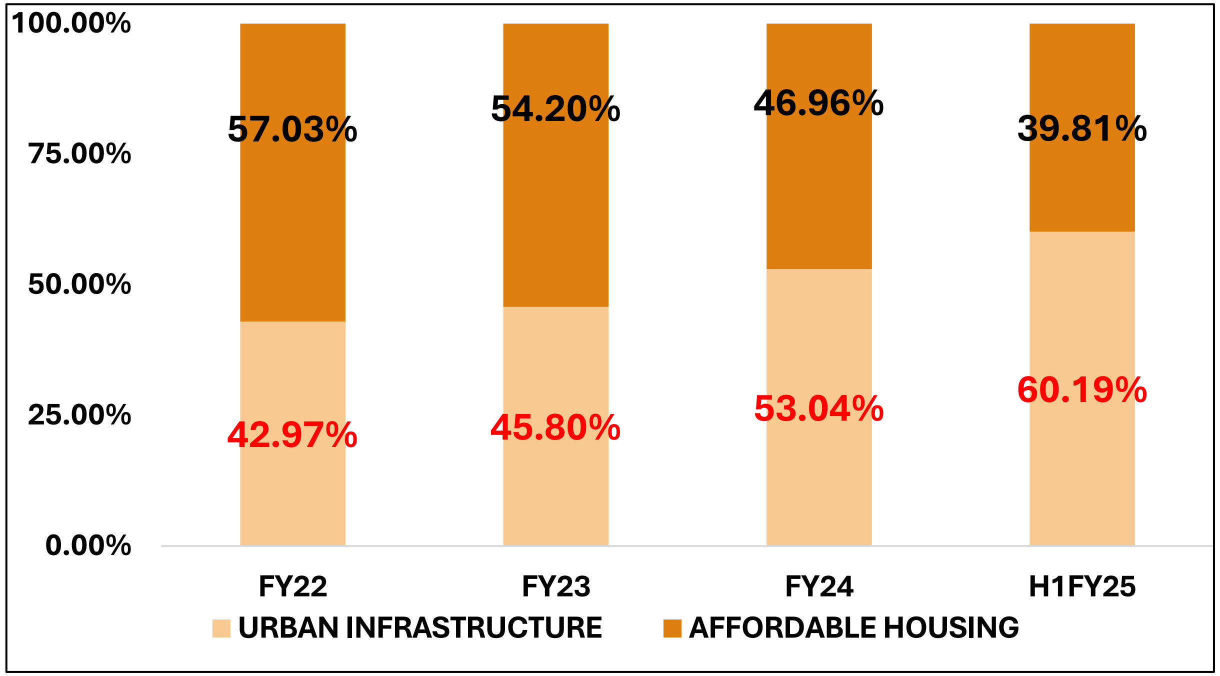

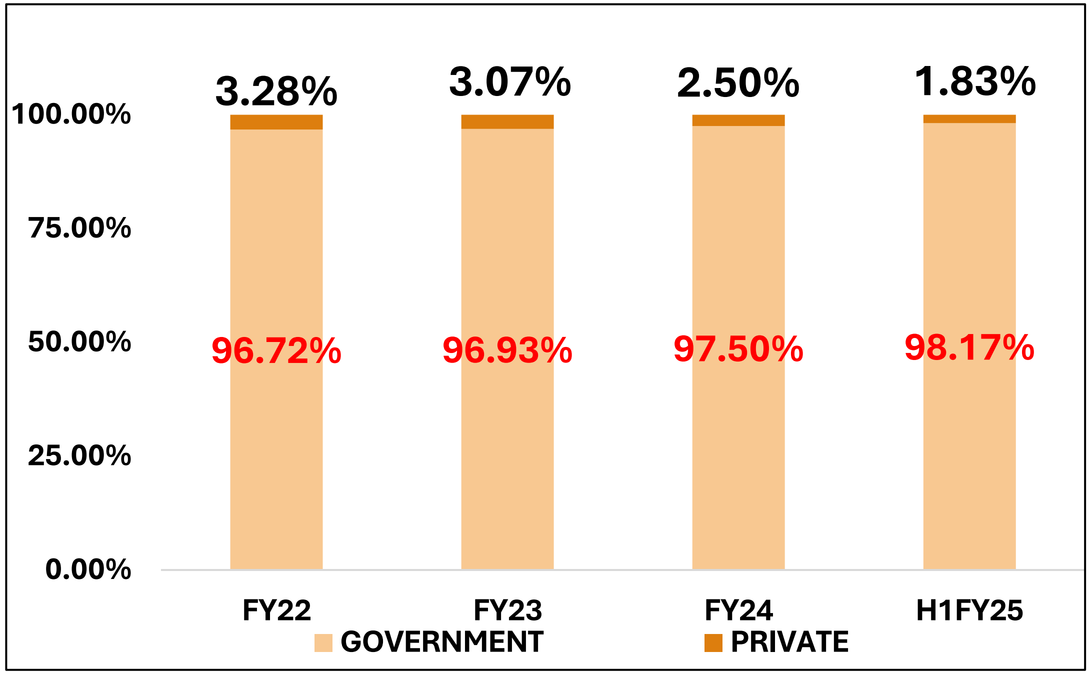

विवरण (₹ करोड़ में)	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	एच 1	
				वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	33,735	36,982	49,143	38,674	66,857
किफायती आवास	44,778	43,761	43,511	42,920	44,211
कुल	78,513	80,743	92,654	81,594	1,11,068
सरकार	75,934	78,267	90,342	79,111	1,09,241
निजी	2,579	2,476	2,312	2,483	2,027

पीएमएवाई 2.0 के साथ किफायती आवास पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी

ऋण स्वीकृतियां

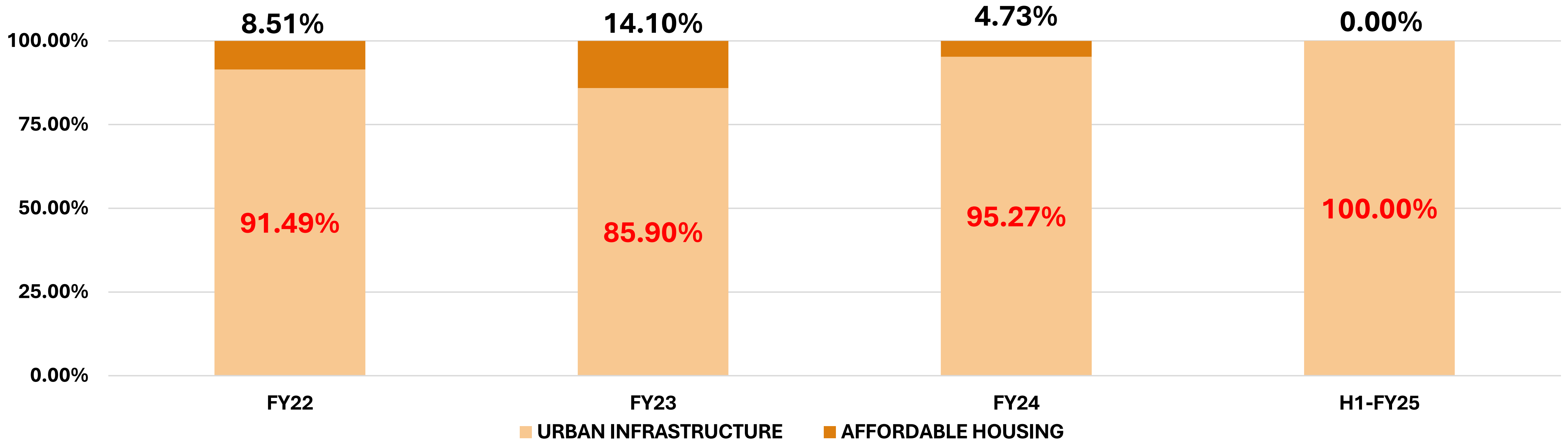

विवरण (करोड़ रुपए में)	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	एच 1	
				वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
शहरी बुनियादी ढांचा	18,904	21,106	78,488	7,435	76,472
किफायती आवास	1,759	3,466	3,899	373	-
कुल	20,663	24,572	82,387	7,808	76,472

वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के दौरान अब तक की सबसे अधिक अर्धवार्षिक मंजूरी

ऋण संवितरण

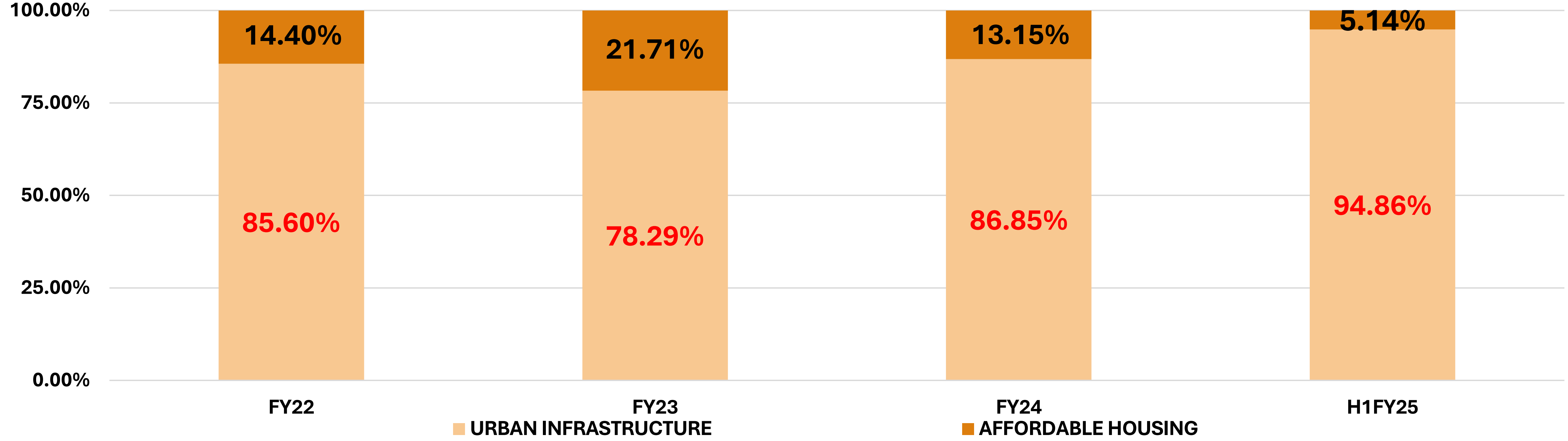

विवरण (करोड़ रुपए में)	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	एच 1	
				वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	7,607	6,628	15,621	3,225	20,583
किफायती आवास	1,280	1,838	2,366	498	1,116
कुल	8,887	8,466	17,987	3,723	21,699

H1FY25 के दौरान अब तक का सबसे अधिक अर्धवार्षिक संवितरण

वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र

बॉरोइंग प्रोफ़ाइल

परिसंपत्ति की गुणवत्ता

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	H1-वित्त वर्ष 25	उधार की औसत लागत	H1-वित्त वर्ष 24	उधार की औसत लागत
A. भारत सरकार के पूर्णतः सेवा बांड	20,000.00	8.47%	20,000.00	8.47%
बी. अन्य				
कर मुक्त बांड	12,372.38	8.04%	14,014.04	8.10%
करयोग्य बांड	15,596.00	7.00%	10,750.00	6.64%
बैंक के ऋण:				
- लघु अवधि	5,165.20	7.20%	2,870.80	6.89%
- मध्यावधि	27,480.63	7.50%	14,941.21	7.73%
- एफसीएनआर(बी)	6,913.18	6.06%	-	-
ईसीबी/ओडीए	5,360.39	5.54%	71.22	8.21%
एनएचबी से पुनर्वित्त सहायता	476.89	5.08%	671.19	5.05%
उप-योग (				

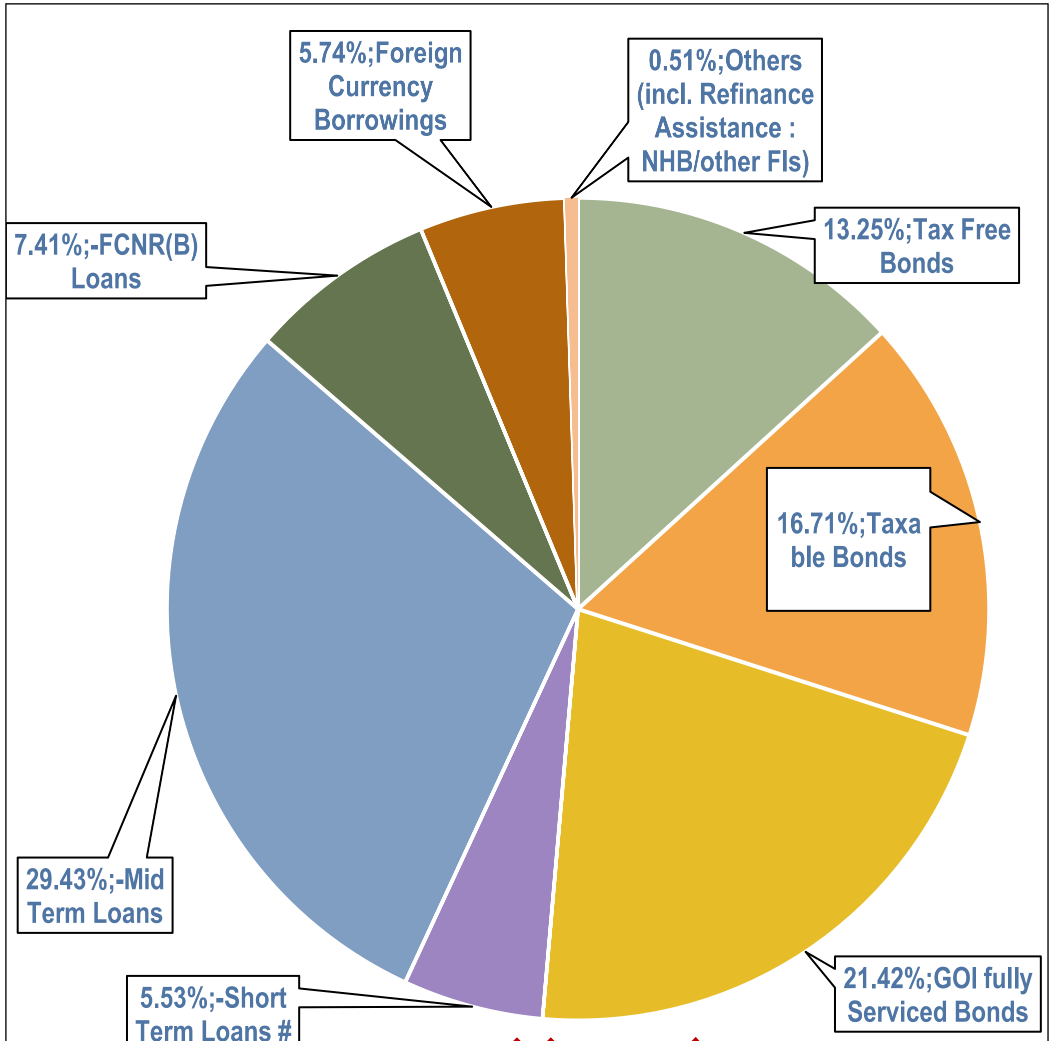

उधार लेने का प्रोफ़ाइल

- व्यवसाय की वृद्धि को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्रोतों के मिश्रण के साथ वित्तपोषण के कई स्रोतों तक पहुंच।

इस अवधि के दौरान जुटाई गई धनराशि

(₹ करोड़ में)

वर्ग	एच 1				12एम			
	वित्त वर्ष 25	औसत लागत	वित्त वर्ष 24	औसत लागत	वित्त वर्ष 24	औसत लागत	वित्त वर्ष 23	औसत लागत
करयोग्य बांड	5,786.00	7.30%	1,500.00	7.48%	1,500.00	7.48%	3,970.00	7.61%
बैंक / एफआईई ऋण								
- लघु अवधि	5,165.20	7.20%	2,870.80	6.85%	6,654.60	7.32%	1,769.50	6.99%
- मध्यम अवधि	9,291.00	7.62%	3,853.50	7.50%	9,002.50	7.55%	10,421.50	7.49%
- एफसीएनआर(बी)	2,923.00	6.20%	-	-	3,990.18	5.96%	-	-
विदेशी मुद्रा	4,471.37	5.51%	-	-	827.85	5.29%	-	-
कुल	**27,636.57**	**6.99%**	**8,224.30**	**7.28%**	**21,975.13**	**7.10%**	**16,161.00**	**7.46%**

₹ जुटाए गए ₹27,636 करोड़ की तुलना में H1 FY25 में इसी H1FY24 में 8,224 करोड़

लागत अनुकूलन के लिए प्रयास

- एएलएम प्रोफाइल के आधार पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विभिन्न स्रोतों से **उधार का विवेकपूर्ण मिश्रण।**
- एफसीएनआर(बी) ऋण 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 6,900 करोड़) @ 6.03%।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित पदचिह्न -** 5 वर्ष की अवधि के लिए 5.50% की दर से ¥ 94 बिलियन (₹ 5,360 करोड़) की ईसीबी उधारी।
- **एफसीएनआर/ईसीबी मार्ग के माध्यम से उधार पर निरंतर ध्यान:**
  - 6% की अपेक्षित लागत पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 4,200 करोड़) का अतिरिक्त एफसीएनआर ऋण लिया जा रहा है।
  - हडको अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशेगा, जिसमें डॉलर/यूरो मूल्यवर्ग में ऋण जुटाने की संभावनाएं तलाशना भी शामिल है।

उधार की कुल लागत

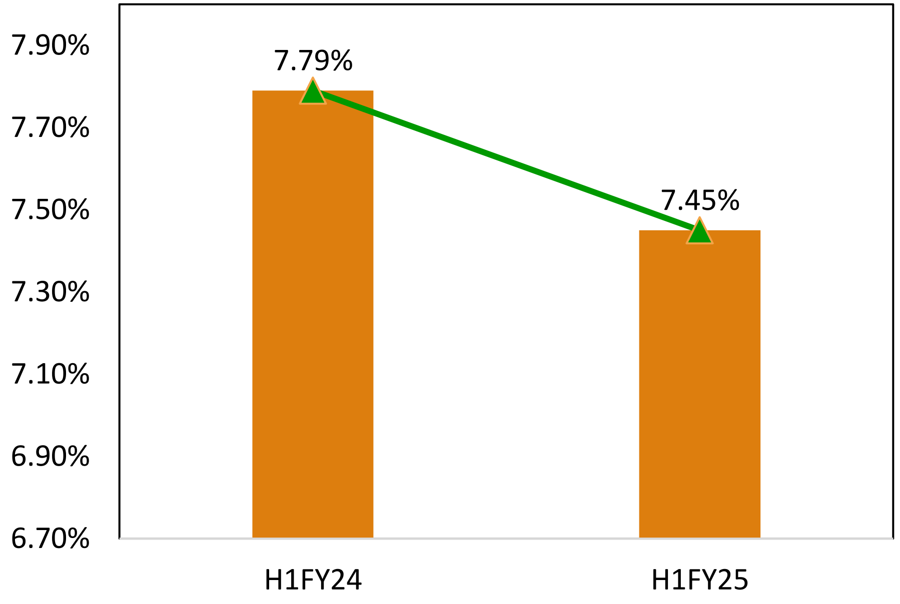

वित्त वर्ष 25 के लिए सकल राजकोषीय घाटा 4.90% रहने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी उधारी में कमी आएगी। इसका आगे चलकर जी.सेक./बॉन्ड प्रतिफल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता

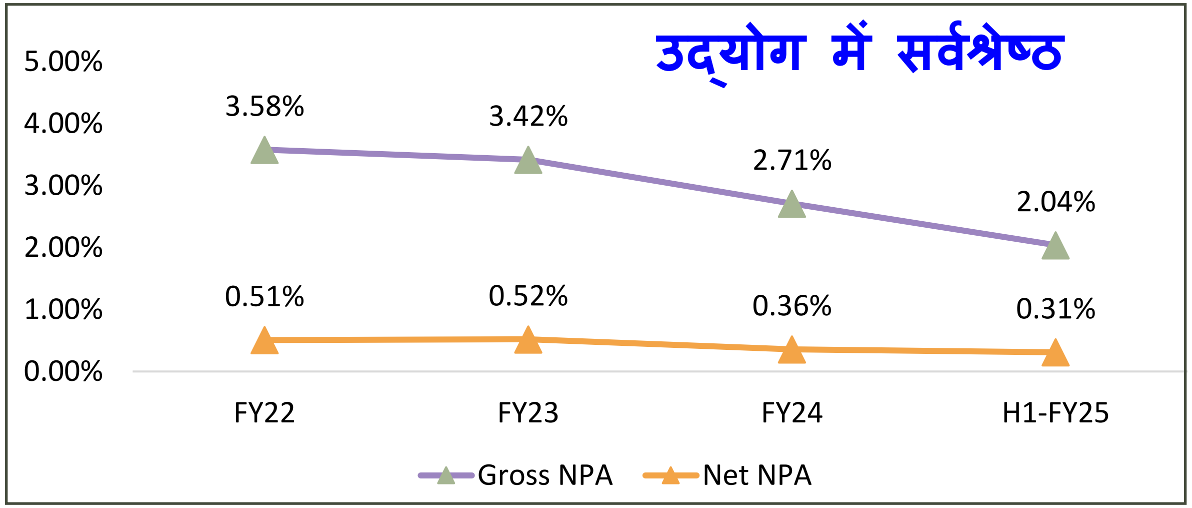

पर्याप्त प्रावधान कवरेज अनुपात (%) [1]

1. प्रावधान कवरेज अनुपात एनपीए ऋणों के विरुद्ध बनाए गए प्रावधान के अनुपात को दर्शाता है

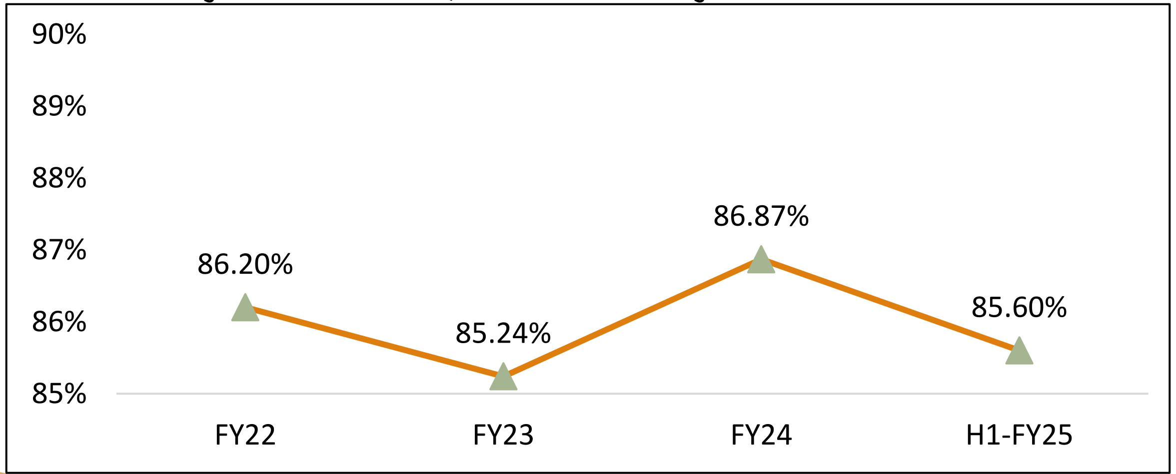

- **मजबूत मूल्यांकन और निगरानी तंत्र**
- **नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा** - सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं के अनुरूप
- **सरकार और उसकी एजेंसियों को ऋण** : ऋण पुस्तिका का 98% हिस्सा सरकार और उसकी एजेंसियों को दिए गए ऋण से बना है।
- **सरकारी गारंटीकृत ऋण** : 77% ऋण राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित हैं।

ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां – समाधान स्थिति

सकल एनपीए ₹ 2270.42 करोड़, शुद्ध एनपीए ₹ 342.84 करोड़, प्रावधान कवरेज 85.60%

कंसोर्टियम परियोजनाएं

- ₹1,257.10 करोड़
- 09 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

एनसीएलटी समाधान के तहत कंसोर्टियम

- ₹ 1222.12 करोड़
- 06 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

एनसीएलटी से बाहर (कंसोर्टियम परियोजनाएं)

- ₹34.98 करोड़
- 03 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

गैर-संघीय परियोजनाएं

एनसीएलटी

- ₹29.78 करोड़
- प्रावधान किया गया – 100%

मुकदमा दायर मामले/डीआरटी

- ₹429.75 करोड़
- शीर्ष 10: ₹ 280.12 करोड़ (65%)
- प्रावधान किया गया – 100%

वित्त वर्ष 25 के दौरान (आज तक) 4 लंबे समय से लंबित एनपीए खातों का समाधान किया गया - ₹ 255.44 करोड़

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	एच1वित्तीय वर्ष 25	वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही	% परिवर्तन - वर्ष दर वर्ष	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	% परिवर्तन वर्ष-दर-वर्ष
1	ऋण स्वीकृति	76,472	7,808	अब तक का सबसे अधिक H1 ऋण स्वीकृतियां	82,387	24,572	235%
2	ऋण संवितरण	21,699	3,723	अब तक का सर्वाधिक H1 ऋण वितरण	17,987	8,466	112%
3	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	1,246.37	897.39	अब तक का उच्चतम H1 PAT, 39%	2,116.74	1,701.62	24%
4	प्रचालन से राजस्व	4,706.07	3,706.41	परिचालन से अब तक का सर्वाधिक H1 राजस्व, 27%	7,784.29	7,049.46	10.42%
5	ऋण पुस्तिका	1,11,068	81,594	36% की वृद्धि	92,654	80,743	15%
6	नेटवर्थ	17,124.35	15,724.40	9% की वृद्धि	16,614	15,445	7.60%
7	ईपीएस	6.23	4.48	39% की वृद्धि	10.57	8.50	24%
8	मार्केट कैप	43,741.52	17,296.42	1 वर्ष में 2.53 गुना से अधिक	37,295	8,618	
9	सकल एनपीए (%)	2.04	3.36	बड़ा सुधार	2.71%	3.42%	
10	शुद्ध एनपीए (%)	0.31	0.49	उद्योग में सर्वश्रेष्ठ	0.36%	0.52%	
11	लाभांश (%)	14.56	11.41	बड़ा सुधार	12.74	11.02	

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रश्न 2		एच 1		12 महीने
	वित्त वर्ष 25 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 24 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 25 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 24 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 24 (लेखापरीक्षित)
आय:					
- प्रचालन से राजस्व	2517.72	1864.80	4706.07	3706.41	7,784.29
- अन्य कमाई	8.42	16.05	17.26	24.71	163.81
कुल आय (1)	2526.14	1880.85	4723.33	3731.12	7,948.10
खर्च:					
- वित्तीय लागत	1662.02	1217.61	3125.85	2409.05	4,963.94
- अन्य लागत	97.23	84.29	164.58	168.70	348.81
- वित्तीय साधनों की क्षति	(233.15)	(27.47)	(251.84)	(50.86)	(208.09)
कुल व्यय (2)	1526.10	1274.43	3038.59	2526.89	5,104.66
कर पूर्व लाभ {3= (1-2)}	1000.04	606.42	1684.74	1204.23	2,843.44
कर व्यय (4)	311.42	154.73	438.37	306.84	726.70
कर के बाद शुद्ध लाभ {5 = (3-4)}	688.62	451.69	1246.37	897.39	2,116.74

महत्वपूर्ण संकेतक

हडको hudco A NAVRATNA CPSE

विवरण	एच1-2025		एच1-2024		वित्त वर्ष 24	
	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर
ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़)	1,11,068	91,068	81,594	61,594	92,654	72,654
ऋण पर प्रतिफल (%)	9.24	9.34	9.34	9.50	9.04	9.09
कोष की लागत (%)	7.46	7.15	7.63	7.25	7.25	6.75
ब्याज प्रसार (%)	1.78	2.19	1.70	2.25	1.79	2.34
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.01	3.66	3.22	4.18	3.18	4.04

विवरण	एच1-2025	एच1-2024	वित्त वर्ष 24
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.54	1.50	1.57
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	5.46	3.84	4.05
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (%) (वार्षिकीकृत)	2.40	2.20	2.42
इक्विटी पर रिटर्न (%) (वार्षिक)	14.56	11.41	12.74
नेट वर्थ (₹ करोड़)	17,124.35	15,724.40	16,614.30
औसत नेटवर्थ (₹ करोड़)	17,198.94	15,811.17	16,029.78
प्रति शेयर ₹ 10 का	85.54	78.55	82.99
प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ में	6.23	4.48	10.57

1. ऋण पर प्राप्ति की गणना ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (एनपीए मामलों के निपटान पर प्राप्त ब्याज सहित) को औसत ऋण परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।
2. निधियों की लागत की गणना ब्याज व्यय को औसत कुल उधार से विभाजित करके की जाती है।
3. ब्याज प्रसार, ऋण पर प्राप्ति और निधियों की लागत के बीच का अंतर है।
4. शुद्ध ब्याज मार्जिन की गणना औसत ब्याज अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों द्वारा ब्याज अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर शुद्ध ब्याज आय के आधार पर की जाती है।
5. ब्याज कवरेज अनुपात की गणना ब्याज और कर से पहले की कमाई को वित्त लागत से विभाजित करके की जाती है।
6. ऋण इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।
7. इक्विटी पर रिटर्न की गणना, अवधि के अंत में शेयरधारकों के फंड द्वारा अवधि के लिए कर के बाद लाभ को विभाजित करके की जाती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
8. औसत परिसंपत्तियों पर रिटर्न (कर के बाद) की गणना अवधि के लिए पीएटी को औसत कुल परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

क्षेत्र दृष्टिकोण और अवसर

2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
और
विकसित भारत @ 2047

(विकसित भारत @ 2047)

पीएमएवाई 2.0 में अवसर और भूमिका

पीएमएवाई 2.0 और संबंधित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन में हुडको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

पीएमएवाई (यू) 2.0

- शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ मकान
- कुल परिव्यय : ₹ 10 लाख करोड़
- **अवयव**
  - लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी)
  - साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)
  - किफायती किराया आवास (ARH)
  - ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)
- **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय**
  - डीपीआर/परियोजनाओं की डेस्क-सह-साइट जांच के लिए तकनीकी एजेंसी के रूप में नामित
  - किफायती मकानों के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय/अवरक्त संस्थाओं तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण
  - कार्यस्थल निरीक्षण
  - आईएसएस के तहत सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)
- **अवसर**
  - राज्य/लाभार्थी हिस्से के लिए प्रतिभाग वित्तपोषण – **₹ 2.20 लाख करोड़**

पीएमएवाई (जी) 2.0

- 2 करोड़ से अधिक मकान - 10 करोड़ व्यक्तियों को लाभ
- कुल परिव्यय: ₹ 3 लाख करोड़ (केंद्र: 2 लाख करोड़ और राज्य: 1 लाख करोड़)
- हडको राज्य के हिस्से के लिए प्रति-भागीय वित्तपोषण उपलब्ध कराएगा

भारत में बुनियादी ढांचे का विकास

1. **क्रिसिल ईयर बुक 2023: भारत 2030 तक सात वित्तीय वर्षों में बुनियादी ढांचे पर लगभग ₹ 143 लाख करोड़ खर्च करेगा, जो 2017 से शुरू होने वाले पिछले सात वित्तीय वर्षों में खर्च किए गए ₹ 67 लाख करोड़ से दोगुना से भी अधिक है।**

(₹ लाख करोड़ में)

क्षेत्र	निवेश 2024-2030 पी
सड़कें	37.30
रेलवे	25.60
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	18.90
अन्य इन्फ्रा	15.0
ऊर्जा	39.10
परिवहन	7.0
कुल	**142.90**

2. **मॉर्गन स्टेनली ने** अपनी हालिया रिपोर्ट, **"द न्यू इंडिया - इन्फ्रास्ट्रक्चर"** में बुनियादी ढांचे के निवेश में 15.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुमान लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप **अगले पांच वर्षों में भारत में संचयी व्यय होने का अनुमान है ।**

हडको की भूमिका – विकास के लिए प्रेरक

हडको को हाल ही में एनबीएफसी-आईएफसी का दर्जा (आरबीआई से) मिला है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त पोषण की कमी को कम करने में हडको की भूमिका और मजबूत होगी।

2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत (2047 तक विकसित भारत) के लिए सरकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित पहलों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त पोषण की भारी मांग पैदा करने के लिए तैयार है:

- **भूमि अधिग्रहण**
- **एकीकृत टाउनशिप और औद्योगिक कोरिडोर्स**
- **गतिशीलता – मेट्रो, एक्सप्रेसवे आदि।**
- **पीएमएवाई, स्मार्ट सिटीज, अमृत, जेजेएम, एसबीएम 2.0**
- **स्वास्थ्य अवसंरचना, हरित अवसंरचना और ऊर्जा परिवर्तन**
- **बंदरगाह वित्तपोषण (बंदरगाह और हवाई अड्डा)**

धन्यवाद

प्रधान कार्यालय:

हडको भवन, कोर-7-ए,

इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003